योगी सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति-2022 युवाओं को देगी भरपूर अवसर

इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग से 10 लाख लोगों को रोजगार

इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह शांत होते हैं। शोर नहीं करते। प्रदूषण भी नहीं होता। इनका एकदम शांत रहना देश में एक नई तरह की क्रांति लेकर आ रहा है। एकदम शांति से मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग से नहीं है बल्कि यह देश में एक मौन क्रांति की शुरुआत है। आज देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसकी कुछ वर्ष पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भारत को अगले 25 वर्षों के अमृत काल में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। इसमें मौन क्रांति की अहम भूमिका होगी।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी भारी सब्सिडी

30,000 करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य

इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग में प्रदेश बनेगा वैश्विक केंद्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति-2022 को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर योगी सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने इसके लिए प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में तकरीबन 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस नीति का उद्देश्य न केवल राज्य में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली को विकसित करना है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी एवं संबंधित उपकरणों के निर्माण के लिए प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र भी बनाना है।

त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था

नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति में त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके तहत उपभोक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए, वाहनों के निर्माण के लिए, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सेवाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं।

नई नीति की प्रभावी अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क में छूट रहेगी।

- यदि इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण राज्य में किया गया है तो समान छूट चौथे और पांचवें वर्ष में भी जारी रहेगी।

15% की सब्सिडी फैक्ट्री मूल्य पर दी जाएगी प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर

वाहन खरीद पर छूट व्यापार को देगा गति

पहले दो लाख दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर पांच हजार रुपये प्रति वाहन, पहले 50,000 तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रति वाहन अधिकतम 12,000 रुपये तक सब्सिडी

पहले 25,000 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति वाहन पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

यूपी को बनाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग हब

भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह जरूरी है कि परंपरागत ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल चलित वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे में प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण करने वाली कंपनियों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। इससे यूपी इलेक्ट्रिक वाहन का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनियों की ओर से प्रस्ताव मिले हैं। यह प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देगा। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में इकाइयों के लिए अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण तथा प्रमाणन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इस कार्य में औद्योगिक संगठनों की सहायता भी ली जाएगी।

– योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

सब्सिडी से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा

राज्य में आरएंडडी एवं परीक्षण सुविधाओं सहित इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी बैटरी और संबंधित कंपोनेंट के सैटेलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए तीन हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करने वाली पहली पांच इलेक्ट्रिक वाहन परियोजनाओं को अधिकतम 500 करोड़ रुपये प्रति प्रोजेक्ट के अंतर्गत 20 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

सरकार की यह पहल प्रदेश में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना में मील का पत्थर साबित होगी। इस नए उद्योग से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों पर निर्भर नहीं रहना होगा।

चार्जिंग एवं बैटरी स्वैपिंग सेवा से भी लोगों को काम

इस नीति के तहत राज्य में दो हजार चार्जिंग एवं बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं को विकसित करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रति प्रोजेक्ट अधिकतम 10 लाख रुपये सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, एक हजार ऐसे स्वैपिंग स्टेशनों की सुविधाओं को विकसित करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को पांच लाख रुपये प्रति स्वैपिंग स्टेशन तक सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है। इस माध्यम से प्रशिक्षित लोगों के सामने रोजगार के नए आयाम सरकार स्थापित कर रही है।

प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही अधिकतम 1000 ई गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन रुपये 1,00,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी।

साल भर में पेट्रोल वाहन जितना सस्ती होने वाली हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां

जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल, डीजल आदि) पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा भी बचेगी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एक साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों की लागत के बराबर होगी। सरकार पेट्रोल और डीजल के बजाए फसल अवशेषों से एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। सरकार की कोशिश रही है कि देश में एक साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों की लागत के बराबर हो जाए। इससे जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल, डीजल आदि) पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाया जा सकेगा।

प्रदेश में ऐसे वाहनों के निर्माण से इसकी लागत में कमी आएगी। सभी उपकरण प्रदेश में ही बनेंगे तो आयात पर खर्च कम होगा।

स्टांप ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी

एकीकृत ईवी परियोजना और अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजना स्थापित करने पर स्टांप ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

मेगा, वृहद, एमएसएमई परियोजना के लिए पूर्वांचल व बुंदेलखंड में 100 प्रतिशत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर मध्यांचल व पश्चिमांचल में 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी। गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में स्टांप ड्यूटी पर 50 प्रतिशत छूट। प्रति परियोजना अधिकतम दस लाख रुपये गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाएगी।

100% स्टांप ड्यूटी में छूट अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजना स्थापित करने पर

पेटेंट पंजीकरण शुल्क घरेलू पेटेंट पंजीकरण पर 50 हजार रुपये और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट पंजीकरण शुल्क पर दो लाख रुपये तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

बैटरी निर्माण पर सब्सिडी बढ़ा रही है अवसर

प्रदेश में एक गीगावॉट की न्यूनतम क्षमता वाला बैटरी निर्माण प्लांट लगाने के लिए 1500 करोड़ रुपये या इससे अधिक का निवेश करने वाली पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं को अधिकतम 1000 करोड़ रुपये के निवेश पर 30 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की इस पहल से प्रदेश में बैटरी निर्माण के कार्य को गति मिलेगी। इस निर्माण कार्य में प्रदेश के प्रशिक्षित युवा तेजी से जुड़ेंगे।

500 करोड़ रुपये या इससे अधिक का निवेश करने वाली पहली पांच मेगा इलेक्ट्रिक वाहन परियोजनाओं, 300 करोड़ रुपये या इससे अधिक का निवेश करने वाली पहली चार मेगा इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी परियोजनाओं को निवेश पर 20 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी।

उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा ईवी चार्जिंग के लिए विशेष टैरिफ आदेश अधिसूचित किया गया है।

सिंगल ऑनलाइन पोर्टल सबकी राह करेगा आसान

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर निर्धारित छूट का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने और इसे सुगम बनाने के लिए योगी सरकार ने परिवहन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया है। नई नीति का लाभ ईवी सेक्टर से जुड़े अन्य लोगों को भी मिल सके इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से एक सिंगल ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मुफ्त रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट का लाभ लोगों को कैसे दिया जाए इसकी विस्तृत योजना विभाग तैयार कर रहा है।

यह भी जानें

- उत्तर प्रदेश भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे अग्रणी राज्य है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीवाश्म ईंधन से संचालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति हेतु देश के समग्र प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तत्पर है।
- वर्ष 2021 में ईवी के विक्रय में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही है, जिसमें सभी श्रेणियों में विक्रय किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 66,701 तक पहुंच गई है।
- माह जुलाई 2022 तक देश में क्रियाशील इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या 13,34,385 का 25 प्रतिशत अर्थात 3,37,180 इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश में गतिशील है।
- भारत सरकार की एफएएमई-1 व 2 योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक रहा है।
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के संबंध में उत्तर प्रदेश में एफएएमई-2 के अंतर्गत 207 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं, जो राज्य के 9 नगरों-नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली एवं झांसी में आरईआईएल एवं ईईएसएल के माध्यम से स्थापित किए जा रहे हैं।
- राज्य में एक्सप्रेसवेज के किनारे और अधिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की संभावना है। साथ ही राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है।
- मुख्य नगरों के प्रमुख मार्गों पर ईवी सार्वजनिक बसों को सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड पर प्रारंभ किया जा रहा है। जिसमें इन मार्गों पर चार्जिंग स्टेशनों का विकास भी सम्मिलित है।